कोटद्वार, बुधवार
27 नवम्बर 2024
वर्षः 46
अंकः 203 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com

स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

हादसे में जख्मी तीसरे युवक की भी मौत

काशीपुर। सोमवार रात को सड़क हादसे में जख्मी युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 26 वर्षीय शाहरुख पुत्र शफीक अहमद के रूप में हुई। हादसे में जख्मी नसीम पुत्र नफ़ीस अहमद की हालत गंभीर है। उसका मुरादाबाद में इलाज चल रहा है। हादसे के दौरान मोहल्ला नई बस्ती रहमत नगर निवासी 27 वर्षीय मो. खालिक पुत्र अमीर हुसैन और 25 वर्षीय आमिर पुत्र असलम की मौके पर ही मौत हो गई थी। मंगलवार शाम तीनों युवकों को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सोमवार रात 11 बजे मोहल्ला नई बस्ती रहमत नगर निवासी मो. खालिक, आमिर, शाहरुख और नसीम अहमद और फैज कार से काशीपुर रोड स्थित टोल प्लाजा पर बनी चाय की दुकान पर चाय पीने जा रहे थे। बीएसवी इंटर कॉलेज से पहले कार अनियंत्रित होकर पास के एक प्लाट की दीवार से टकराकर उछल गई। जिससे कार के परखच्चे उड़ गये। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों ने किसी तरह घायलों को निकालकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मो. खालिक और आमिर को मृत घोषित कर दिया। आधी रात के बाद शाहरुख को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों को काशीपुर और मुरादाबाद में भर्ती कराया गया। घायल नसीम की हालत गंभीर है। प्रभारी निरीक्षक जगदीश ढकरियाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के फुटेज आ गए है। तीन युवकों के मरने और दो के घायल होने की सूचना है। बताया कि तेज गति की कार दीवार की नींव से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई है। मृतकों के शव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। तीनों युवक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। खालिक पैथलैब, शाहरुख पीओपी तो आमिर रेडीमेड की दुकान पर काम करता था। शाहरुख के दो बच्चे हैं।

कूड़ा विवाद में किशोरी समेत चार महिलाओं पर फेंका तेजाब

रुड़की। कूड़े के मामूली से विवाद को लेकर आरोपियों ने पड़ोस की महिलाओं पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले में एक किशोरी समेत चार महिलाएं झुलस गईं। आनन फानन में परिजनों ने महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला कटहेड़ा में एक 16 वर्षी किशोरी इल्मा अपने घर के बाहर से कूड़ा एकत्रित कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस के ही कुछ लोगों ने कूड़ा उनके घर के बाहर फेंकने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। इससे पहले की महिलाएं कुछ समझ पाती आरोपियों ने उन पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गिरने के बाद किशोरी इलमा व चार अन्य महिलाएं झुलस गई। आसपास के लोगों ने तेजाब अटैक में झुलसी महिलाओं को मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवार ने बताया कि तेजाब में झुलसी किशोरी व महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दून व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को मिले एक दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर

देहरादून। दून और हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों को एक दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर मिल गए है। एचएनबी मेडिकल विवि के कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने डॉक्टरों के चयन को मंजूरी दी। इसके बाद अब सरकार ने इन डॉक्टरों को दोनों ही कॉलेजों में तैनाती दे दी है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि दून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक दर्जन नई नियुक्तियां की गई हैं। इससे कॉलेजों के संचालन में मदद के साथ ही मरीजों व मेडिकल के छात्रों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि दून में प्लास्टिक सर्जरी में डॉ. आकाश सक्सेना, गायनी में डॉ. नेहा कचरू, रेडियोडाग्नोसिस में डॉ. राहुल कुमार सिंह, एनेस्थिसिया में डॉ. विजिता पाण्डेय, बर्न यूनिट में डॉ. राजदीप बिन्द्रा, इमरजेंसी मेडिसिन मे डा. नवजोत का चयन हुआ है।

एकनाथ शिंदे ने दिया सीएम पद से इस्तीफा

देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बन गई सहमति!

मुंबई,महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि 29 नवंबर को प्रदेश में नई सरकार गठित की जाएगी. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं. वहीं, महायुति के गठबंधन दल बीजेपी, शिवसेना (शिंदे), एनसीपी (अजित पवार) की बात करें तो सभी पार्टियों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी की लहर के सामने कोई नहीं टिक पाया. बीजेपी ने अकेले 132 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, उनकी सहयोगी पार्टियों में एनसीपी ने 41 और शिंदे की पार्टी ने 57 सीटों पर कब्जा जमाया. दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी महज 50 सीटों पर सिमट कर रह गई. जिसमें शिवसेना (उद्धव ठाकरे) ने 20, कांग्रेस 16, शरद पवार की पार्टी 10 और अन्य सहयोगी दलों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. इस भारी बहुमत के बाद से महायुति के कार्यकर्ताओं में तो जोश देखा ही जा रहा है कि लेकिन अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा. हालांकि जानकारी की मानें तो महायुति दल के सभी पार्टियों ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है. देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर खिंचतान भी सामने आ रही है. बता दें कि भारी बहुमत से जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि विधायक दल की बैठक में ही यह फैसला लिया जाएगा कि कौन महाराष्ट्र का नया सीएम बनेगा. महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और इसी फॉर्मूले के साथ प्रदेश में नई सरकार बनेगी. जानकारी के अनुसार, आज शाम तक आधिकारिक तौर पर भी सीएम के नाम की घोषणा की जा सकती है.

चुनाव आयोग ने जारी की राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना

नईदिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी तक शपथ नहीं ली है. इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए भी अधिसूचना जारी दी. मंगलवार (26 नवंबर) को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा. बता दें कि देश के किसी ना किसी कोने में हर साल चुनाव होते हैं. जिन्हें कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है. बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों पर 20 दिसंबर को मतदान कराने का ऐलान किया है. जबकि चुनावी नतीजे भी इसी दिन यानी 20 दिसंबर को ही जारी कर दिए जाएंगे. बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकार पांच वर्ष का होता है. संसद के उच्च सदन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है.

जम्मू—कश्मीर में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस

● सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी

नईदिल्ली,75वें संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है. दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू–कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया. पीएम मोदी ने कहा, हमारा संविधान देश की हर अपेक्षा और जरूरत पर खरा उतरा है. संविधान की ताकत के कारण ही आज बाबा साहब का संविधान जम्मू–कश्मीर में पूरी तरह लागू हो पाया है. पहली बार जम्मू–कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया. आज भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान हमें रास्ता दिखा रहा है. यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन गया है. सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे. वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेंगी, चुनौतियां बदलेंगी. इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा. बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया. 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब हम स्मरण कर रहे हैं, तब ये भी नहीं भूल सकते कि आज के ही दिन मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है. इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं. मैं देश का यह संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार और धार्मिक समानता पर याचिका खारिज की

के.ए. पॉल ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली, प्रसिद्ध वैश्विक शांति कार्यकर्ता और प्रजा शांति पार्टी के संस्थापक डॉ. के.ए. पॉल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जनहित याचिका खारिज किए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की। यह याचिका चुनावी प्रक्रिया, धार्मिक प्रशासन और भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुधार की मांग कर रही थी। डॉ. पॉल ने इस याचिका पर खुद बहस की, लेकिन कोर्ट ने इसे कुछ ही मिनटों में खारिज कर दिया और सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया।याचिका की प्रमुख मांगेंः

–1. *चुनावी सुधारः*

डॉ. पॉल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के स्थान पर मतपत्र (बैलट पेपर) के उपयोग की मांग की। उन्होंने कहा, दुनिया के 197 में से 180 देश, जिनमें 50 यूरोपीय देश और अमेरिका भी शामिल हैं, मतपत्र से चुनाव कराते हैं। फिर भारत ईवीएम पर क्यों निर्भर है, जो छेड़छाड़ योग्य है? उन्होंने इस संदर्भ में एलन मस्क, वाईएस जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया।

2. *धार्मिक प्रशासन में सुधारः*

डॉ. पॉल ने मांग की कि तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू पुजारियों को सौंपा जाए, जैसे चर्च का संचालन पादरी और मस्जिद का संचालन मौलवी करते हैं। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर की अनुमानित संपत्ति ?4 लाख करोड़ बताई और आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन और धन का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है।3. *विधायकों की दलबदल पर कार्रवाईः–डॉ. पॉल ने निर्वाचित विधायकों द्वारा दलबदल पर चिंता जताई और 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल विरोधी कानून के सख्त पालन की मांग की।

उन्होंने तेलंगाना में कई विधायकों के व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने के मामलों को उजागर किया।डॉ. पॉल ने अपनी याचिका खारिज किए जाने पर आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन की बात करने वाली मेरी याचिका को बिना पर्याप्त सुनवाई के खारिज कर दिया गया। लोकतंत्र में न्यायपालिका आखिरी उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं दिया। यह न्याय का बड़ा अपमान है।डॉ. पॉल ने भारत में चुनावी पारदर्शिता के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ज्यादातर देश पारदर्शिता के लिए मतपत्र का इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मंदिर प्रशासन को लेकर चल रहे विवादों पर बोलते हुए डॉ. पॉल ने कहा, हिंदू पुजारियों को भी चर्च के पादरियों और मस्जिद के मौलवियों की तरह अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तिरुपति बालाजी, जो वैटिकन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, को विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

यूपी में गिरा अंग्रेजों के जमाने का पुल, गंगा नदी में समाया; सामने आया वीडियो

उन्नाव,यूपी के उन्नाव जिले में मंगलवार की भोर में अचानक एक पुल गिर गया। बताया जा रहा है कि ये पुल अंग्रेजों के जमाने में बना था। हालांकि इस पुल पर कई सालों से यातायात को बंद कर दिया गया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ब्रिटिश कालीन इस पुल को चार साल पहले ही बंद कर दिया गया था। ये पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया था। मंगलवार तड़के पुल का एक हिस्सा अचानक गंगा नदी में गिर गया। इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय निवासी आशू अवस्थी ने बताया कि मंगलवार भोर में दो बजे के बाद पुल के दो खंभों के बीच का हिस्सा गंगा नदी में गिर गया। स्थानीय निवासियों का दावा है यह पुल 1874 में अवध एंड रूहेलखंड रेलवे लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया था। वहीं स्थानीय निवासी पंडा राजू ने बताया कि पुल को 2021 में दरारें आने के बाद यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कानपुर की तरफ से 2, 10, 17 और 22 नंबर की कोठियों में गहरी दरारें पाई गई थीं, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 5 अप्रैल 2021 को इस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया था।

हेमंत सोरेन को एमपी—एमएलए कोर्ट से झटका

—ईडी के समन की अवहेलना मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज

रांची, ईडी के समन की अवहेलना के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची की एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ईडी की ओर से इस मामले में दायर मुकदमे में हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई को अदालत में याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायतवाद दायर की है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए। एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 11 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से बुलाया है और चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से भेजे गए समन का उल्लंघन किया। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है।

भू कानून की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू

भू कानून का उल्लंघन करने वालों ने स्थानीय लोगों को जमीनें बेचना किया शुरू

देहरादून। उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन पर जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। जमीनें सरकार में निहित की जा रही है। इससे डरे भू माफियाओं और राज्य में गलत तरीके से जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों ने जमीनों को स्थानीय लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे राज्य से बाहर के लोगों से जमीनें न खरीदें। भू–कानून का उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। अपर सचिव राजस्व आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में मौजूदा भू–कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन स्तर से लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाई के बीच ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि राज्य से बाहर के लोग, जिन्होंने पूर्व में भू–कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी हैं, वे अब इन जमीनों को राज्य के लागों को ही बेच रहे हैं। ऐसा कर वे जमीनों को सरकार में निहित होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। जिस व्यक्ति ने एकबार भू कानून का उल्लंघन कर लिया है, तो वो जमीन सरकार में निहित होकर ही रहेगी। भले ही वो राज्य के स्थानीय निवासी को ही क्यों न बेच दी हो। कहा कि स्थानीय जनता से अपील की जाती है कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह से जमीन का सौदा न करें। ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का कोई वित्तीय नुकसान न हो।

रजिस्ट्री के दौरान जिलों में बरती जाए सतर्कता

अपर सचिव राजस्व ने बताया कि जिला स्तर पर रजिस्ट्रियों के दौरान सतर्कता बरतने को कहा गया है। राज्य से बाहर के लोग जो जमीनें बेच रहे हैं, उन पर विशेष नजर रखी जाए। देखा जाए कि ऐसी जमीनें भू कानून का उल्लंघन कर तो नहीं खरीदी गई। या जिन प्रयोजनों के लिए इन जमीनों को मंजूरी लेकर खरीदा गया था, वो काम हुए या नहीं। ऐसे मामलों में यदि जमीनों को स्थानीय लोगों को बेचा जा रहा है, तो रजिस्ट्री के दौरान ही सख्ती बरती जाए। ताकि भू–कानून का उल्लंघन करने वाले लोग राज्य के निवासियों को जमीनें बेच कर वित्तीय नुकसान न पहुंचा पाएं। विवादित जमीन खरीदने से स्थानीय लोगों को दोहरी दिक्कत होगी। पहली जमीनें सरकार में निहित होने पर वित्तीय नुकसान होगा।

भारत का संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, संविधान दिवस पर बोले राहुल गांधी

नईदिल्ली, आज देश के संविधान को अंगीकार हुए 75 साल हो गए. इस मौके पर देशभर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं. इस मौके पर पुराने संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम सांसद मौजूद रहे. इस दौरान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत हुई जो पूरे साल चलेगा. बता दें कि देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने भी भी संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की. जो अगले साल 26 जनवरी तक चलेगा. इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि, संविधान एक किताब नहीं है ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की सामाजिक सशक्तिकरण की सोच है वो इसके अंदर है. राहुल गांधी ने आगे कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण जो सोच है, अंबेडकर जी की, फुले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की वो इसके अंदर है आप किसी भी राज्य में चले जाइए, केरल में नारायण गुरू, कर्नाटक में बसवनाजी, फुलेजी, शिवाजी महाराज हर राज्य में आपको ऐसे दो तीन नाम मिलेंगे,

बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल, हिंदुओं पर फिर हुए हमले

ढाका, बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, इस दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 50 से अधिक हिंदू समुदाय के लोग घायल हुए हैं। ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण सभा के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों और चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुशाल बरन पर भी हमला हुआ है। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए है। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है।

चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें में कहा, हमें चिंताजनक खबर मिली है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्कॉन भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने की अपील करता है। हम एक शांतिपूर्ण भक्ति आंदोलन हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्ण दास को जल्द रिहा करे। हम भगवान कृष्ण से इन भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। बता दें कि, इसी साल 30 अक्तूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोप है कि 25 अक्तूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने आठ सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी।

प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज, 13 जनवरी को शुरू होगा आयोजन

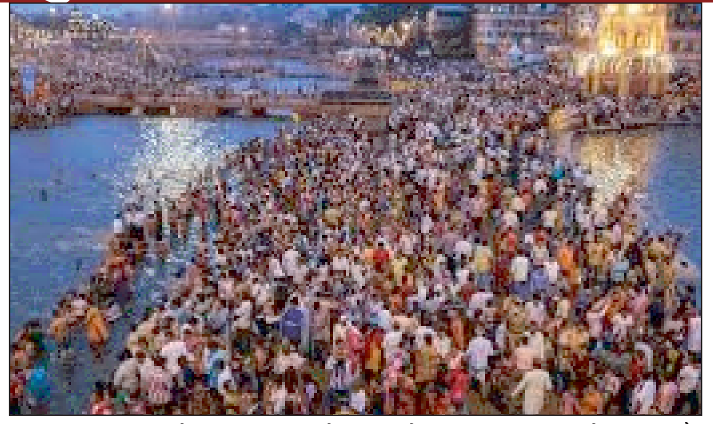

प्रयागराज, पौष पूर्णिमा के दिन यानी 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और इस दिन पहला शाही स्नान भी होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान के साथ समापन भी हो जाएगा। महाकुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर किया जाएगा। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को स्वयं यहां चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महाकुंभ के लिए 238 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं में महाकुम्भ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ–साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वच्छाग्रहियों एवं सफाईकर्मियों को यूनिफॉर्म किट तथा नाविकों को लाइफ जैकेट समेत विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित करेंगे। इससे पूर्व सीएम योगी विभिन्न धार्मिक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ के तौर पर प्रस्तुत करने पर सर्वाधिक जोर दे रही है। इसी वजह से यहां विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसे सीएम स्वयं हरी झंडी दिखाएंगे। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले सीएम नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण करेंगे। कंट्रोल रूम के साथ ही अन्य परियोजनाओं और सफाई उपकरणों को भी सीएम द्वारा लोकार्पित किया जाएगा।

इन सभी परियोजनाओं की लागत करीब 14 करोड़ रुपए होगी। इसके अतिरिक्त सीएम योगी परेड मेला क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में स्वच्छता उपकरणों (टिपर, कॉम्पैक्टर आदि) का भी अनावरण करेंगे, जिसकी कुल लागत 50.38 करोड़ रुपए है। यही नहीं, सीएम 173 करोड़ रुपए के फायर, जल पुलिस, रेडियो, यातायात के उपकरणों का भी अनावरण करेंगे। इस तरह सीएम योगी महाकुंभ 2025 में सुरक्षा, स्वच्छाग्रहियों एवं गंगा सेवा दूतों के लिए 237.38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन उपकरणों के माध्यम से महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। एक तरफ सीएम योगी स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का अनावरण करेंगे तो दूसरी ओर वह महाकुंभ को स्वच्छ बनाने में जुटे स्वच्छाग्रहियों व सफाई कर्मियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी करेंगे। इसके तहत सीएम योगी करीब 20 हजार स्वच्छाग्रहियों व सफाई मित्रों को यूनिफॉर्म किट तथा नाविकों को लाइफ जैकेट प्रदान करेंगे। इसी तरह, स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत 15 हजार से अधिक कर्मियों (10 हजार कार्मिक, 3 हजार नविक और अन्य) को 5 से अधिक योजनाओं से भी जोड़ने का काम करेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक करेंगे रूस का दौरा

नईदिल्ली,रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले महीने रूस के दौरे पर जा रहे हैं। वे 8 से 10 दिसंबर तक राजधानी मॉस्को और रूसी शहर कैलिनिनग्राद में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री यहां परियोजना 11356 फ्रिगेट के ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे और इसे भारतीय नौसेना को हस्तांतरित करेंगे।इस दौरान मॉस्को में शीर्ष भारतीय रक्षा अधिकारी अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव के साथ वार्ता करेंगे। हालांकि, अभी भारत की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस–भारत ने नवंबर 2018 में 4 परियोजना 11356 फ्रिगेट की डिलीवरी के लिए समझौता किया था।इस समझौते के तहत, 2 फ्रिगेट रूस के कैलिनिनग्राद में बाल्टिक शिपयार्ड यंतर में और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे।प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट को समुद्री जल–तट दोनों में दुश्मन के सतही जहाजों और पनडुब्बियों से निपटने और हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।फ्रिगेट तोपखाने, मिसाइल, विमान–रोधी प्रणालियों, टारपीडो आयुध से लैस हैं।

सम्पादकीय

अल्पसंख्यक श्रेणी का अधिकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्म के आधार पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी करने के संविधान विरोधी प्रयासों पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस से सवाल किया है, ह्यक्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि वे संविधान में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को कम करके इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो उसने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एससी/एसटी आरक्षण को कम कर इस कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। यह कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004–2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। मोदी ने अब फिर से आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लोगों का धन छीन कर अपने खास लोगों को बांटने की साजिश रची है। यह अत्यंत तल्ख टिप्पणी राजस्थान के टोंक जिले में एक चुनावी जनसभा में की। प्रधानमंत्री की टिप्पणी संपूर्ण सत्य है। एक समय कांग्रेस सरकार की अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की मंशा रही थी। लेकिन सवीच्च न्यायालय ने भी कड़ा रु ख अपनाते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरु द्ध दायर अपील को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए कि उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह तो कोटे में उपकोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा। दरअसल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ संविधान के विरु बताया था। वर्तमान में दिसम्बर, 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने ओबीसी के कोटे में खास तौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे कानूनी रूप देते हुए ह्यअल्पसंख्यकों से संबंधित और अल्पसंख्यकों के लिए जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। वंचित समुदाय, चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, को बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है क्योंकि बदहाली की सूरत अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता, आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं, और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालत करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी। वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म–समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं लेकिन जैन समुदाय केंद्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल, ह्यअल्पसंख्यक श्रेणीह्ण का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक निहितार्थ हैं, इन्हें समझना मुश्किल है।

सरकार और समाज को हाथी की प्रति संवेदनशील बनना होगा

पंकज चतुर्वेदी

मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में एक साथ दस हाथियों के मारे जाने से दुनिया सन्न है। इनमें ना मादा थी और दो गर्भवती। और इस तरह दो हाथियों की मौत भ्रूण में भी हो गई।

इसके ठीक तीन दिन पहले पास के छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में तीन हाथी मारे गए तो कहा गया कि उन पर 11 केवीए की बिजली का तार गिर गया था। रविवार रात छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल से 1 हाथी के बिछड़ने की जानकारी मिली और सोमवार सुबह जंगल के किनारे स्थित धान के खेत में हाथी का शव मिला। हाथी का शव मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि खेत के चारों तरफ बिजली का तार लगाया गया था।

खेत मालिक ने हाथी को मारने के लिए हाईवोल्टेज बिजली तार में क्लच वायर से जोड़ कर करंट लगाया था जिसकी चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। इस खुलासे के बाद वन विभाग ने आरोपी मुरका निवासी रामबक्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी राज्य में 12 नवम्बर को बेहद मार्मिक घटना सामने आई जब रायपुर में सीतानदी–उदंती टाइगर रिजर्व में हाथी का एक बच्चा पोटाश बम से घायल हो गया। उसके मुंह और पैर से खून बह रहा था और वह जलन से बचने को इधर–उधर पानी में शरीर डाल रहा था। यह बम जंगली सूअरों के शिकार के लिए उपयोग किया जाता है।

दुर्भाग्य है कि बांधवगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में हाथी की मौत के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और गुस्साए हाथियों ने वहीं गांव के तीन लोग कुचल कर मार डाले। बीते कुछ सालों में हाथी के पैरों तले कुचल कर मरने वालों की संख्या बढ़ी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम , केरल, कर्नाटक सहित 16 राज्यों में बिगडैल हाथियों के कारण इंसान से टकराव बढ़ रहा है। इस झगड़े में हाथी भी मारे जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि बांधवगढ़ में बड़ी संख्या में हाथियों की मौत कुछ विषाक्त खाने से हुई है। शक इस बात से खड़ा होता है कि राज्य सरकार के कुछ अफसर इसे तुरत–फुरत जहरीली कुटकी खाने से मौत निरूपित कर रहे थे लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात से असहमति जताई कि जंगल का जानवर क्या किसी वन–उत्पाद खाने से मरेगा तो हड़बड़ाहट हुई। वन महकमे के अफसर सस्पेंड हुए।

खेत मालिक ने हाथी को मारने के लिए हाईवोल्टेज बिजली तार में क्लच वायर से जोड़ कर करंट लगाया था जिसकी चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। इस खुलासे के बाद वन विभाग ने आरोपी मुरका निवासी रामबक्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी राज्य में 12 नवम्बर को बेहद मार्मिक घटना सामने आई जब रायपुर में सीतानदी–उदंती टाइगर रिजर्व में हाथी का एक बच्चा पोटाश बम से घायल हो गया। उसके मुंह और पैर से खून बह रहा था और वह जलन से बचने को इधर–उधर पानी में शरीर डाल रहा था। यह बम जंगली सूअरों के शिकार के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य है कि बांधवगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में हाथी की मौत के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और गुस्साए हाथियों ने वहीं गांव के तीन लोग कुचल कर मार डाले। बीते कुछ सालों में हाथी के पैरों तले कुचल कर मरने वालों की संख्या बढ़ी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम , केरल, कर्नाटक सहित 16 राज्यों में बिगडैल हाथियों के कारण इंसान से टकराव बढ़ रहा है। इस झगड़े में हाथी भी मारे जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि बांधवगढ़ में बड़ी संख्या में हाथियों की मौत कुछ विषाक्त खाने से हुई है। शक इस बात से खड़ा होता है कि राज्य सरकार के कुछ अफसर इसे तुरत–फुरत जहरीली कुटकी खाने से मौत निरूपित कर रहे थे लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात से असहमति जताई कि जंगल का जानवर क्या किसी वन–उत्पाद खाने से मरेगा तो हड़बड़ाहट हुई। वन महकमे के अफसर सस्पेंड हुए।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली की ओर से म्प्र वन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हाथियों के विसरा में माइक्रो टॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड मिलने की पुष्टि हुई है। एफीसीसीएफ और म्प्र वन विभाग की ओर से गठित एसआईटी के प्रमुख एल कृष्णमूर्ति के मुताबिक, आईवीआरआई ने विसरा सैंपल की विषाक्तता रिपोर्ट से पता चलता है कि हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो पौधे/अनाज खाए थे। हालांकि, विसरा सैंपल में मिला साइक्लोपियाजोनिक एसिड कितना जहरीला था और कितनी मात्रा में था, क्या वही मौत का कारण हो सकता है–इसकी आगे जांच अभी जारी है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जंगल और वनोपज आय के बड़े माध्यम हैं, लेकिन बाघ के लिए जम कर खर्च करने वाली सरकार हाथी के लिए लापरवाह रही है। प्रदेश में हाथियों के प्रबंधन के लिए सिर्फ एक करोड़ सालाना का बजट वन विभाग के पास है। प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रदेश का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच रहता है, लेकिन हाथियों के प्रबंधन पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए वन विभाग ने इस साल 66 लाख रुपये रखे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरु आत 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी जो अभी देश के 16 राज्यों में चल रहा है। हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी और इनके शिकार को रोकने के लिए शुरू की गई योजना में प्राकृतिक आवासों को सुधारना, हाथी–मानव संघर्ष को नियंत्रित करना सहित कई काम किए जाते हैं लेकिन वन विभाग के पास बजट होता नहीं है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सहेज कर रखने में गजराज की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण–मित्र पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। जंगली हाथियों के बस्तियों में घुसने को किसी राज्य की सीमा से बांधा जा नहीं सकता। आंकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि करीबी राज्य ओडिशा के हालात हाथियों को लेकर इतने खराब हैं कि दंतैल और गुस्सैल हो गए जंगली हाथी छत्तीसगढ़ और झारखंड में अपनी खीज मिटा रहे हैं।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलुरु के एक अध्ययन में बताया गया था कि ओडिशा में उपलब्ध जंगल और संसाधन में अधिकतम 1700 हाथी भली प्रकार जी सकते हैं, जबकि आज यहां गजराज की संख्या 2100 से अधिक है। इस तरह 400 से अधिक हाथियों के लिए भोजन, पानी और आने पर्यावासीय संकट सामने दिख रहा है। सरकारी रिकार्ड में है कि 2017–18 और 4 नवम्बर, 2024–25, ओडिशा में 634 मारे गए, जिनमें 22 का शिकार हुआ, एक को जहर दिया गया 91 जानबूझकर बिजली के झटके से, 32 आकस्मिक बिजली करंट से मारे गए, जबकि 28 हाथी रेल से टकरा कर काल के गाल में गए। इसी साल 58 हाथियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं।

जानना जरूरी है कि हाथियों को 100 लीटर पानी और 200 किलो पत्ते, पेड़ की छाल आदि की खुराक जुटाने के लिए हर रोज 18 घंटों तक भटकना पड़ता है। हाथी दिखने में भले ही भारी–भरकम हैं, लेकिन उनका मिजाज नाजुक और संवेदनशील होता है। थोड़ी थकान या भूख उसे तोड़ कर रख देती है। ऐसे में थके जानवर के प्राकृतिक घर यानी जंगल को जब नुकसान पहुंचाया जाता है तो मनुष्य से उसकी भिड़ंत होती है।

2018 में पेरियार टाइगर कन्जर्वेशन फाउंडेशन ने केरल में हाथियों के हिंसक होने पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन रिपोर्ट में पता चला कि जंगल में पारंपरिक पेड़ों को काट कर उनकी जगह नीलगिरी और बबूल बोने से हाथियों का भोजन समाप्त हुआ और यही उनके गुस्से का कारण बना। पेड़ों की ये किस्म जमीन का पानी भी सोखती हैं, सो हाथी के लिए पानी की कमी भी हुई। पयार्वरण–मित्र पर्यटन और और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। हाथी की उपस्थति स्वस्थ जंगल की निशानी है, अच्छा जंगल धरती पर इंसान के लिए अनिवार्य है। अब सरकार और समाज, दोनों को हाथी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा।

अमेरिकी इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत ट्रंप की जीत

अवधेश कुमार

डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने का विश्लेषण अभी लंबे समय तक जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ अमेरिका ने भी इतिहास रच दिया। हर चुनाव में एक पक्ष जीतता और दूसरा हारता है लेकिन इसके मायने होते हैं।अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विजय और डेमोक्रेट कमला हैरिस की पराजय के साथ अमेरिकी इतिहास में एक नए दौर की शुरु आत हुई है।

जिस डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में केवल डेमोक्रेट ही नहीं उनकी अपनी पार्टी, मीडिया, पूंजीपतियों, थिंक टैंक, विविद्यालयों आदि का एक बड़ा समूह समाप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा चुका हो, वह वापस आकर इन सबको चुनौती दे और जीत का झंडा गाड़ दे तो इसे किसी दृष्टि से साधारण घटना नहीं माना जा सकता। मतदान समाप्त होने के साथ ही ट्रंप ने लिखा कि आज रात अमेरिका के लोगों ने बदलाव के लिए स्पष्ट जनादेश दिया।ट्रंप और कमला हैरिस के बीच माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। परिणाम ने इसे गलत साबित कर दिया। ट्रंप ने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाया और कमला हैरिस पिछले चुनाव में बिडेन के मत की भी बराबरी नहीं कर पाई। 2020 में जिस जॉर्जिया से ट्रंप अत्यंत कम अंतर से हारे थे जब वहां का परिणाम उसके पक्ष में गया, फिर नॉर्थ कैरोलिना से उनके समर्थन का परिणाम आया तो लग गया कि अमेरिकी जनता का राजनीति और देश को लेकर मनोविज्ञान बदला है।स्विंग माने जाने वाले अन्य राज्यों पेंसिलवेनिया, एरीजोना, मिशीगन, विस्कांसिन और नेवाडा में भी हैरिस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। ट्रंप ने इलेक्टरल के अलावा पॉपुलर मतों के मामले में भी सफलता पाई जो उनके 2016 की जीत से अलग कहानी बताती है।अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने 1992 के बाद ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया था। अमेरिकी इतिहास में केवल 1892 में ग्रोवर क्लब्लैंड ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 4 वर्ष के बाद फिर से चुने गए। इस तरह ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। वास्तव में अनेक दृष्टि से यह असाधारण परिणाम है। ट्रंप को लोकतंत्र विरोधी, फासिस्ट साबित करने के लिए विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।आपराधिक आरोप के मुकदमे भी चले। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार हुआ जब डेमोक्रेटिक ने अंतिम दौर में जो बाइडेन को उम्मीदवारी के दौर से हटाकर कमला हैरिस को सामने लाया। धन के मामले में भी कमला हैरिस ट्रंप से बहुत आगे निकल गई। मीडिया ने ऐसा वातावरण बनाया मानो ट्रंप पिछड़ चुके हैं।परिणाम क्या आया? राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं सीनेट में भी रिपब्लिकन को बहुमत मिला तथा प्रतिनिधि सभा में बेहतर स्थिति में आए। इसका निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के लोगों ने ऐसा जनादेश दिया ताकि ट्रंप अपनी घोषणाओं या एजेंडे में किसी तरह के बड़े अवरोध का सामना करने से बचे रहे। समाज के जिस वर्ग का समर्थन डेमोक्रेट को मिलने की परंपरा रही है उनमें भी ट्रंप प्रवेश कर चुके हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार महिलाओं का मत कमला हैरिस के पक्ष में झुका रहा, लेकिन बाइडेन को प्राप्त मतों से वह पीछे ही रही।अेतों, लैटिन अमेरीकियों, एशियाई समूहों में से भी लगभग एक तिहाई मतदाताओं ने ट्रंप के लिए वोट किया। हां, ेत मतदाताओं के समर्थन में थोड़ी कमी आई। ये सारे तथ्य बताते हैं कि अमेरिकी जनमानस ट्रंप को लेकर कितना बदला है। सच कहें तो ट्रंप ने रिपब्लिकनों के साथ देश की सोच बदलने तथा राजनीति में नए चेहरों को खड़ा करके जीत सुनिश्चित की। डेमोक्रेट स्वयं को अति वामपंथी या लिबरल साबित करने के लिए जो कुछ करते रहे उसे आम लोगों ने सहजता से स्वीकार नहीं किया।आश्चर्यजनक रूप से शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों का समर्थन रिपब्लिकन में बढ़ा है। डेमोक्रेट एलिट व शिक्षित वर्ग के एक समूह तथा हॉलीवुड एवं थिंक टैंक के बीच अपनी पहचान की व नीति के लिए सिमटती गई है। लोगों ने माना कि वे जो आवाज उठा रहे हैं वह अमेरिका की सामूहिक भावना नहीं है। बाइडेन के कार्यकाल में आंतरिक रूप से अमेरिका कमजोर हुआ, वैश्विक स्तर पर भी उसकी छवि धूमिल हुई। हालांकि सर्वेक्षणों में अधिकतर मतदाताओं की चिंता वैश्विक या विदेश नीति नहीं थी। यानी अमेरिकी लोगों की प्राथमिकताएं बदली है। ट्रंप का 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' यानी 'मागा' लोगों के दिलों में गया। अवैध घुसपैठ, बढ़ती महंगाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध एवं अस्थिरता को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया और लोगों को अपील कर गया।

वस्तुतः 2021 में ही दिखा था कि अमेरिका में ट्रंपवाद का नया दौर शुरू हो चुका है जिसका व्यापक समर्थन है, परंपरागत डेमोक्रेट, एलिट, अति लेफ्ट लिबरल राजनीति का समर्थन घट रहा है। अमेरिकी चुनाव अभियान में ट्रंप केंद्रित ठीक वैसे ही परिदृश्य ,आरोप–प्रत्यारोप एवं मुद्दे थे जो हम भारत में देखते हैं। यानी ट्रंप का आना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता–धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, संविधान कमजोर होगा और वैश्विक स्तर पर युद्ध एवं तनाव का खतरा ज्यादा बढ़ेगा।

दुर्दशा का तथ्य नकारना व्यर्थ

देहाती इलाकों में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों की संख्या में साढ़े चार प्रतिशत इजाफा हुआ है। 2016–17 के सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या 47.40 प्रतिशत थी, जो ताजा सर्वे के समय 52 फीसदी हो चुकी थी। एक और सरकारी संस्था की रिपोर्ट ने श्रमिक वर्ग की बढ़ती रही दुर्दशा पर रोशनी डाली है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे (एनएएफआईएस) 2021–22 के दौरान पाया गया देहाती इलाकों में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों की संख्या में साढ़े चार प्रतिशत इजाफा हुआ है।

2016–17 के सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की संख्या 47.40 प्रतिशत थी, जो ताजा सर्वे के समय 52 फीसदी हो चुकी थी। कहा जा सकता है कि अब ज्यादा लोग लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। मगर आय की स्थिति पर गौर करें, तो ऐसे तर्क निराधार मालूम पड़ेंगे। ताजा सर्वे में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 12,698 रु. सामने आई। इसमें पांच साल में डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तब औसत आमदनी 8,059 रु. थी। राष्ट्रीय परिवार 4.4 व्यक्तियों का है। तो हर व्यक्ति पर आय 2,886 रु. बैठती है। यानी प्रति दिन एक व्यक्ति की खर्च क्षमता 96 रुपये होगी।यह औसत आय है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के सबसे धनी और गरीब दोनों तबकों की आमदनी शामिल है। 2013–14 में रंगराजन समिति ने भारत की गरीबी रेखा 32 रु. प्रति दिन खर्च क्षमता रखने का सुझाव दिया था। दस साल की मुद्रास्फीति से उसे एडजस्ट करें, तो ये रकम आज तकरीबन 60 रुपये बैठेगी। इस पैमाने पर पर अनुमान लगाएं, तो संभव है कि भारत में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। वैसे, जिन परिवारों की औसत आय 12 हजार रुपये हो, वे लाइफ स्टाइल संबंधी चीजों की खरीद के लिए कर्ज लें, यह मानने का कोई तुक वैसे भी नहीं है। तो जाहिर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी–विवाह आदि जैसे खर्चों के लिए कर्ज लेने वाले परिवार बढ़े हैं। इसके पहले लेबर ब्यूरो की पारिश्रमिक दर सूचकांक रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय के जारी हुए आंकड़ों, तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आदि में बताया जा चुका है कि श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय गिरी है और औसत आय में वृद्धि गतिरुद्ध हो गई है। उपभोग और मांग गिरने की बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में दुर्दशा का तथ्य नकारना व्यर्थ है।

चौथे वीकेंड पर कार्तिक की भूल भुलैया 3 ने अजय देवगन की सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ा

अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 एक साथ दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दोनों फिल्मों ने तीन हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. नई फिल्में रिलीज होने के बावजूद दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखी. साउथ स्टार सूर्या की कंगुवा रिलीज होने के बावजूद सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 ने बेहतर प्रदर्शन किया. हालांकि चौथे वीकेंड पर कार्तिक की फिल्म ने बेहतर प्रदर्शन किया और सिंघम अगेन को कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का कलेक्शन.

अजय देवगन की सिंघम अगेन ने रिलीज के 23वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.60 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 238.55 करोड़ रुपये हो गया. सिंघम अगेन ने 43.5 करोड़ के ओपनिंग कलेक्श के साथ जबरदस्त शुरुआत की थी. इस शनिवार को सिंघम अगेन की टोटल हिंदी में ऑक्यूपेंसी 17.80त्न रही. इसके साथ ही सिंघम अगेन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 360 करोड़ के आसपास हो गया है. भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 23वें दिन 2.60 करोड़ की कमाई की और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 243.60 करोड़ रुपये हो गया है. यानि कार्तिक आर्यन की फिल्म का कलेक्शन सिंघम अगेन से ज्यादा है. भूल भुलैया 3 ने 35.5 करोड़ के ओपनिंग कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी और एक हफ्ते में 150 करोड़ का कलेक्शन किया था. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो भूल भुलैया ने लगभग 370 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है. फिल्म का बजट 150 करोड़ के आसपास है. वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के साथ का फायदा कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 जमकर उठा रही है. फिल्म ने शुरुआत से बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा है. फिल्म 250 करोड़ रुपये की कमाई के करीब है और उम्मीद है कि यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक के रूप में बनकर उभरेगी.

पारिवारिक कारणों से ऑस्ट्रेलिया दौरा बीच में छोड़ भारत वापस लौटेंगे गंभीर

नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं। टीम इंडिया 30 नवंबर से कैनबरा में प्रधानमंत्री इलेवन के खिलाफ होने वाले दो दिवसीय अभ्यास मैच में मुख्य कोच के बिना मैदान में उतरेगी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों से गंभीर स्वदेश लौट रहे हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले उनके ऑस्ट्रेलिया लौटने की संभावना है।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर निजी कारणों से भारत लौट आए हैं, लेकिन 6 दिसंबर को एडिलेड में होने वाले डे–नाइट टेस्ट से पहले उनके टीम से जुड़ने की उम्मीद है। कैनबरा में होने वाला अभ्यास मैच हालांकि दिन में खेला जाएगा, लेकिन इसमें गुलाबी कूकाबुरा गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा।

पाकिस्तान ने बचाई अपनी लाज, दूसरे वनडे में 10 विकेट से दर्ज की जीत

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच में वापसी करते हुए जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तानी गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के चलते जिम्बाब्वे को 145 के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद सैम अयूब के नाबाद शतक की बदौलत पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 18.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

तीन मैच की वनडे सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 80 रन से हराया था। इसके चलते पाकिस्तान टीम की खूब आलोचना हुई। दूसरे वनडे मैच में पाक टीम ने दमदार वापसी की। मेजबान जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे ही ओवर में यह फैसला गलत साबित हो गया।

शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई जिम्बाब्वे

तैय्यब ताहिर ने 6 के स्कोर पर टी मारुमनी को आउट कर टीम को पहला झटका दिया। इसके बाद अबरार ने जे गम्बी को क्लीन बोल्ड कर टीम को दूसरा झटका दिया। जिम्बाब्वे 97/5 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। ऐसे में डायोन मायर्स (33) और सीन विलियम्स (31) ने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। इन दोनों के अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अबरार अहमद ने घातक गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 33 रन देकर चार बल्लेबाजों का शिकार किया। आगा सलमान ने 7 ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। सैम अयूब और फैसल अकरम को एक–एक विकेट मिला।

सैम अयूब ने जड़ा शतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। धैर्य के साथ खेलते हुए सैम अयूब ने शतक जड़ा। अयूब ने 62 गेंद पर नाबाद 113 रन की पारी खेली। इसमें 17 चौके और तीन छक्के शामिल रहे। वहीं, अब्दुल्ला शफीक ने 48 गेंद पर नाबाद 32 रन की पारी खेली। इस पारी में चार चौके शामिल रहे।

बॉक्स ऑफिस पर कंगुवा ने टेके घुटने, बुरी तरह फ्लॉप होने की राह पर सूर्या की फिल्म

साउथ स्टार सूर्या की कंगुवा 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सूर्या के साथ इसमें बॉबी देओल ने भी अहम रोल प्ले किया है. मेकर्स ने फिल्म पर काफी खर्चा किया है इसीलिए फिल्म का बजट 300–350 करोड़ है. लेकिन ये बजट वसूलना फिल्म के लिए भारी पड़ रहा है. जिस तरह सूर्या की फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सामने आ रहे हैं फिल्म ज्यादा दिन थिएटर में नहीं चल पाएगी. आज सूर्या को थिएटर में रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं आइए जानते हैं कंगुवा का 10वें दिन का कलेक्शन.

सूर्या और बॉबी देओल स्टारर फैंटेसी ड्रामा ने 24 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था जो कि एक अच्छी शुरुआत थी लेकिन उसके बाद से फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है. पिछले तीन दिनों से कंगुवा की बॉक्स ऑफिस कमाई केवल 1 करोड़ के आसपास ही रुकी हुई है. दसवें दिन की बात करें तो कंगुवा ने 10वें दिन लगभग ? 1.10 करोड़ की कमाई की है. दसवें दिन की कमाई के साथ ही फिल्म का 10 दिनों का टोटल कलेक्शन ? 66.10 करोड़ हो गया है यानि दूसरे वीकेंड में भी कंगुवा ? 100 करोड़ का कलेक्शन करने में असफल रही. सूर्या और बॉबी देओल की कंगुवा 350 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई है. कंगुवा को लेकर मेकर्स की उम्मीदें काफी ज्यादा थी. एक पैन इंडिया फिल्म और बड़े बजट की फिल्म होने की खातिर कंगुवा से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी लेकिन पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग करे के बाद कंगुवा की कमाई का ग्राफ नीचे गिरता ही जा रहा है. फिल्म को रिलीज को 10 दिन पूरे हो चुके हैं वहीं दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म ने कोई बढ़त नहीं दिखाई. ऐसे में कहना मुश्किल है कि कंगुवा इतने बड़े बजट को वसूल कर पाएगी या नहीं. कंगुवा को शिवा ने निर्देशित किया है. इसे ग्रीन स्टूडियो और यूवी क्रिएशन ने प्रोड्यूस किया है.

टैक्स फ्री होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई द साबरमती रिपोर्ट

विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. लेकिन ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले से ही चर्चा में बनी हुई है. रिलीज के बाद फिल्म ने भले ही शानदार ओपनिंग ना की हो लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसकी तारीफ की है.

देश के कई राज्यों में द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री भी हो गई है जिसके बाद फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो गई है. फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक द साबरमती रिपोर्ट ने पहले हफ्ते 14.3 करोड़ रुपए कमाए थे. दूसरे शुक्रवार फिल्म ने 1.86 करोड़ कमाए थे. वहीं अब दूसरे शनिवार द साबरमती रिपोर्ट ने कुल 2.6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब विक्रांत मैसी की फिल्म ने कुल 18.99 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. बता दें कि देश के कई राज्यों की सरकारों ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है.

आईपीएल 2025: मेगा नीलामी में बिके 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली, सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित आईपीएल 2025 की नीलामी में कई रिकॉर्ड तोडऩे वाले सौदे देखने को मिले। 72 खिलाडिय़ों पर 467.95 करोड़ रुपये खर्च करने के साथ, फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमों को मजबूत करने के लिए पैसे लुटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। नीलामी का मुख्य आकर्षण ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस स्टार विकेट कीपर को 27 करोड़ रुपये में खरीदा।

ऋषभ पंत (27 करोड़, लखनऊ): ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा। लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों के खिलाफ बोली लगाई, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स अपने पूर्व कप्तान को वापस पाने की होड़ में सबसे आगे थी। पंत, 111 मैचों में 3,284 रन और 148.9 की स्ट्राइक रेट के साथ एक शानदार बल्लेबाज हैं। साथ ही वह एक अच्छे कप्तानी विकल्प हैं, जो लखनऊकी बल्लेबाजी लाइनअप को मजबूत करेगी और नए कप्तान की तलाश को खत्म कर सकती है। श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये, पंजाब): कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में आईपीएल खिताब जिताने वाले श्रेयस अय्यर, अब पंजाब किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे। पंजाब ने 26.75 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर उन्हें खरीदा है।

इस बोली में पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता ने हिस्सा लिया था। अय्यर ने सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल 2024 में मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद पंत ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अपनी निरंतरता के लिए माने जाने वाले अय्यर ने 116 मैचों में 3,127 आईपीएल रन बनाए हैं।

एक नजर

कहानी प्रतियोगिता में ऐश्वर्या व प्रिया ने मारी बाजी

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी में मंगलवार को स्टैंर्ड क्लब द्वारा मानकों से फायदों को लेकर कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें ऐश्वर्या व प्रिया ने पहला, दिशा व काजल ने दूसरा, सृष्टी व सारिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान छात्राओं को भारतीय मानक ब्यूरो की जानकारियां दी गई। स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका पंत ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर दिया। स्कूल की प्रधानाचार्य सावित्री नेगी व क्लब मेंटर कांति किमोठी छात्राओं को मानकों की विस्तार से जानकारी दी।

जन संवाद कार्यक्रम दो दिसंबर को

जयन्त प्रतिनिधि। रूद्रप्रयाग : जन समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में आगामी दो दिसंबर को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर दर्ज शिकायतों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय अवकाश को छोड़कर प्रत्येक सोमवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जन संवाद/जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा भी की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सुशासन के दृष्टिगत जन संवाद तथा जन समस्याओं के समाधान की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु आगामी 02 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से जन संवाद/जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल

जयन्त प्रतिनिधि। रूद्रप्रयाग : आगामी निकाय चुनावों में न केवल महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों का आरक्षण होगा अपितु जनपद रुद्रप्रयाग में दो नगर निकायों अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा के निर्वाचन संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में ही होगी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नगर निकाय चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी और सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी महिलाएं हों। जनपद रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा में इन अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनीता पंवार जिला विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि नगर पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी होंगी, जबकि सुनीता अरोड़ा जिला समाज कल्याण अधिकारी, मोनिका चुनेरा, सहायक निबंधक, सहकारी समितियां सपना तिवाड़ी, सहायक विकास अधिकारी उद्यान, ऊखीमठ सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगी। इसी तरह नगर पंचायत तिलवाड़ा के लिए मीनल गुलाटी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग रिटर्निंग अधिकारी, तथा प्रगति चैहान सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गोखले मार्ग में फल विक्रेता ने महिला से की अभद्रता, युवक को डंडों से पीटा

● महिला की ओर से बाजार पुलिस चौकी में दी गई फल विक्रेता के खिलाफ तहरीर ● घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने नगर निगम में किया प्रदर्शन, बाहरी लोगों को बढ़ाने का आरोप

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कोटद्वार के बीच शहर में स्थित गोखले मार्ग में अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को एक फल विक्रेता ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए उसके देवर को डंडों से पीटा। घटना के बाद आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद ने नगर निगम में पहुंचकर सरकारी सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि नगर निगम व स्थानीय प्रशासन बाहरी लोगों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लाख शिकायतों के बाद भी लोगों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। वहीं, पीड़ित महिला ने फल विक्रेता के खिलाफ बाजार चौकी में तहरीर दी है।

सिम्मलचौड़ निवासी संतोषी देवी ने सोमवार शाम गोखले मार्ग से अनार खरीदे थे। अधिकांश अनार खराब होने के बाद वह उन्हें वापस करवाने के लिए गोखले मार्ग में पहुंची थी। लेकिन, फल विक्रेता अनार वापस करने के बजाय संतोषी देवी से ही अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर फल विक्रेता ने महिला व उसके देवर से मारपीट की। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन व निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए गोखले मार्ग को रेहड़ी-ठेली व फड वालों के कब्जे से मुक्त करवाया। साथ ही नगर निगम में धरना देने के बाद कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। बताया कि शहर में सब्जी व फल बेचने के लिए सैकड़ों की संख्या में बाहरी व्यक्ति पहुंच रहे हैं। लेकिन, सरकारी सिस्टम आज तक इनका सत्यापन नहीं कर पाया। नतीजा, अब यह व्यक्ति महिलाओं के साथ भी अभद्रता करने लगे हैं। पूर्व में हुई घटनाओं के बाद भी सिस्टम सुध लेने को तैयार नहीं है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो सत्यापन के अभाव में पुलिस व प्रशासन के हाथ खाली ही रहेंगे। इस मौके पर सौरभ नौडियाल, सचिव, सौरभ आदि मौजूद रहे।

कोटद्वार के गोखले मार्ग में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के सदस्य व अन्य

विद्यालयों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर

जयन्त प्रतिनिधि । कोटद्वार : अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संगठन ने प्रदेश सरकार से सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाना चाहिए। सतपुली में संगठन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी शिक्षकों का एकजुट होना आवश्यक है। निजी हितों को दरकिनार करते हुये सांगठनिक संकल्प एवं सर्व शिक्षक हितार्थ कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर मंडलीय मंत्री बाल मनोज रावत ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के मुद्दे ज्वलंत है, सरकार को विनियमितिकरण हेतु शीघ्र प्रयास करना होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो तदर्थ शिक्षक आंदोलन की राह पर खड़ा होगा। प्रांतीय मंत्री सुनील धस्माना ने कहा कि सरकार का रूख अशासकीय विद्यालयों के प्रति अस्पष्ट का है। जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कैंतुरा ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में निरन्तर मानवीय संसाधन कम होते जा रहे है, सरकार को जल्द से जल्द भर्तियां करनी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष हेमन्त रावत ने कहा कि संगठन को हमेशा परहित के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा और अशासकीय विद्यालय की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बैठक के अंत में संगठन के संरक्षक व पूर्व जिलाध्यक्ष स्व. जनार्दन बुड़ाकोटी व मरचूला बस दुर्घटना हादसे के शिकार शिक्षक स्व. दिलबर सिंह रावत के आसामयिक निधन पर शोक जताते हुए उनकी आत्मा की शांति को प्रार्थना की गई। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र घनशेला, कृष्ण कुमार बलोधी, अनसुया प्रसाद द्विवेदी, गिरीश गौनियाल, संजय कुमार, सौरभ बिष्ट आदि मौजूद रहे। संचालन जिलामंत्री एमबी सारंग ने किया।

फाउंडेशन ने वर-वधु को दिया पौधा

वर-वधु को पौधा देते सदस्य

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वदेशी भारत फाउंडेशन की ओर से वर-वधु को वट, बरगद व पीपल के पौधे भेंट किए गए। इस दौरान सदस्यों ने पर्यावरण के लिए घर-घर अभियान चलाने का भी संकल्प लिया। कहा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़कर कार्य करें।

सदस्यों ने नव वर-वधु उमेश रावत व सृष्टि को पौधे भेंट किए। संस्था के अध्यक्ष धीरेंद्र सागर गढ़वाली ने कहा कि हमें शुभ कार्यों पर पौधा रोपण करना चाहिए। इसको देखते हुए ही वर-वधु को पौधे भेंट किए जा रहे हैं। कहा कि बिना पर्यावरण संरक्षण हम धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस मौके पर मनोज भंडारी, विमल कोटियाल, तनिष्का, उमेश रावत, सृष्टि रावत आदि मौजूद रहे।

निखिल मिस्टर व दिव्या बनीं मिस फ्रेशर

आईएचएमएस कोटद्वार कालेज में आयोजित की गई फ्रेशर पार्टी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पीटेलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज (आईएचएमएस) कॉलेज की ओर से आयोजित फेशियर पार्टी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समारोह में समा बांधा। इस अवसर पर कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने पर निखिल को मिस्टर फ्रेशर और दिव्या को मिस फ्रेशर-2024 का खिताब दिया गया।

मंगलवार को बलभद्रपुर स्थित कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम का कॉलेज के एमडी बीएस नेगी, एजुकेशन सोसाइटी की सदस्य पूर्णिमा नेगी, ईडी अजयराज नेगी, डायरेक्टर एडमिन कर्नल बीएस गुसाईं ने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्रा परिधि, श्रेया, वैदही, दीपिका, मेघा, इशिका, समीक्षा, दिव्या, रानी, साक्षी, खुशी, अदिति, अंशिका, छात्र अभय, सुधांशु, अनुज, विकास, निखिल, शिवम नेगी ने नृत्य, गीत, कविता और कहानियों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से सबका मन मोहा। इस अवसर पर विभिन्न खेल और टैलेंट प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें छात्रों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। कंप्यूटर साइंस के सीनियर छात्राओं और जूनियर छात्राओं के समूह नृत्य ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रैंप पर कैट वाक प्रतियोगिता रही। जिसमें अभय, सुधांशु, नील, तुषार, परिधि, वैदही, दिव्या और शाक्षी ने रैंप पर कैटवाक कर अपने जलवे बिखेरे। निर्णायकों के द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अभय को मिस्टर परफॉर्मेंस और वैदही को मिस परफॉरमेंस जबकि निखिल को मिस्टर और दिव्या को मिस फ्रेशर का खिताब दिया गया। कॉलेज के एमडी बीएस नेगी और पूर्णिमा नेगी ने विजेताओं को शैसे, क्राउन और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक डॉ. अश्वनि शर्मा, जन संपर्क अधिकारी नरेश थपलियाल सहित सभी प्राध्यापक और कर्मचारी मौजूद रहे।

आईएचएमएस में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते छात्र

लोकतंत्र का सुंदर श्रृंगार है हमारा संविधान

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र में संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को देश में संविधान के महत्व के बारे में बताया। वहीं, कांग्रेस ने संविधान की सुरक्षा का संकल्प लिया।

मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह रावत व सुधा असवाल ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संविधान के बारे में बताया। कहा कि जब देश में धर्म, संप्रदाय व वर्गों में भेदभाव किया जा रहा है। तब संविधान ही प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए।

इस मौके पर वीरेंद्र सिंह रावत, गोपाल सिंह गुसाईं, नरेंद्र सिंह नेगी, कृपाल सिंह नेगी, संदीप रावत, राजा आर्य, जावेद, प्रदीप नेगी, सुरेंद्र सिंह गुसाईं, महावीर सिंह, मनोज रावत, चंद्रमोहन सिंह रावत, एमडी खान, प्रवीन कुमार, विनोद नेगी, सूरज प्रसाद कांति, भारत सिह बिष्ट आदि मौजूद रहे।

वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में प्राचार्य प्रो. डॉ. डी. एस. नेगी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी प्राचार्य प्रो. डॉ. बसंतिका कश्यप ने छात्र-छात्राओं को संविधान के बारे में बताया। कहा कि 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इस मौके पर डा. संत कुमार, डा. ऐश्वर्या राणा, डा. आदेश कुमार, डा. अभिषेक गोयल, डॉ. संतोष कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं, बीरोंखाल के दुर्गम विद्यालय राऊ मावि थपला में विद्यार्थियों को संविधान के महत्व के बारे में बताया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक महिपाल रावत, विजय रावत, संतोष नेगी आदि मौजूद रहे। वहीं, नवयुग स्कूल में संविधान दिवस पर पेंटिंग व वाद-विवाद प्रतियोगिता के साथ ही भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य नीलम नेगी ने कहा कि संविधान लोकतंत्र का श्रृगार है।

संविधान दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते विद्यार्थी

होटल के कमरे में ठहरे युवक ने किया विषाक्त का सेवन

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नजीबाबाद रोड स्थित एक होटल के कमरे में ठहरे युवक ने विषाक्त का सेवन कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी। पुलिस युवक के स्वजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

घटना मंगलवार दोपहर करीब एक बजे की है। सोमवार रात करीब आठ बजे युवक ने नजीबाबाद रोड स्थित एक होटल में कमरा किराए पर लिया। मंगलवार दोपहर तक जब युवक कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल संचालक ने कमरे को खोला तो वहां युवक बेड़ पर बेसुध पड़ा हुआ था। संदेह होने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बेड पर विषाक्त की सीसी भी पड़ी हुई थी। पुलिस व होटल संचालकों ने युवक को बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को होटल संचालक ने बताया कि युवक सोमवार रात करीब आठ बजे होटल में पहुंचा था। कमरा लेते समय उसने सोमवार को लैंसडौन जाने की बात कही थी। कमरा लेने से पूर्व युवक ने अपनी आईडी होटल में जमा करवाई थी। बताया कि होटल में जमा करवाई गई आईडी के आधार पर युवक की पहचान हरियाणा के जिला झज्जर के अंतर्गत ग्राम धुरना निवासी दीपक कुमार पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में हुई। बताया कि युवक के मोबाइल फोन के आधार पर स्वजनों को सूचना दी गई है।

दस खाद्य कारोबारियों पर लगाया 6 लाख 43 हजार का जुर्माना

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : मिथ्या छाप, अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करने पर दस खाद्य कारोबारियों पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ईला गिरि के न्यायालय ने 6 लाख 43 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला अभिहीत अधिकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पौड़ी एएस रावत ने बताया कि विभाग की ओर से न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में 10 वाद दायर किए गए थे। न्याय निर्णायक अधिकारी ने इन मामलों में फैसला सुना दिया है। उन्होंने बताया कि दो अलग-अलग स्थानों से हिन्दुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा निर्मित रेड लेवल नेचुरल केयर चाय के नमूने लेकर खाद्य विश्लेषक रुद्रपुर को भेजे गए। जांच में नमूने मिथ्या छाप (मिस ब्रांडेड) घोषित किए गए। न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य पदार्थों के मिथ्या छाप पाए जाने पर संबंधित कंपनी पर 01-01 लाख रुपये का जुर्मा ना लगाया। उन्होंने बताया कि अमूल गोल्ड होमोनाइज्ड स्टैन्डराइज्ड पैकेट बंद दूध का नमूना जांच में अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के तहत निर्धारित वसा की मात्रा कम पाई गई। न्याय निर्णायक अधिकारी ने संबंधी कंपनी पर दो लाख रुपये अर्थदंड लगाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पौड़ी बाजार की एक दुकान से विक्र्ी धनिया पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूना अधोमानक मिला। जिस पर न्यायालय ने धनिया पाउडर पैकिंग करने वाली कंपनी जीएल एग्रो कॉरपोरेशन गुजरात और मार्केटिंग करने वाली कंपनी गंगाराम लालूदास पटेल गुजरात को 35-35 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए। जबकि संबंधित दुकानदार के बिल प्रस्तुत न करने पर उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। रावत ने बताया कि सात खाद्य कारोबारियों पर बिना खाद्य लाइसेंस बिक्री करने और साफ-सफाई न होने पर एक लाख 73 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया। उक्त समस्त खाद्य कारोबारियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जुर्माने की धनराशि न्याय निर्णय अधिकारी पौड़ी के पक्ष में चेक अपना ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी ई-ऑफिस को गंभीरता से लें : डीएम

ऑनलाइन बैठक में डीएम डॉ. आशीष चौहान अधिकारियों को निर्देश देते हुए।

माइक्रो लेवल पर प्लान बनाते हुए राजस्व वसूली करें

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने भू-कानून संबंधी मामलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि संबंधी लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी ई-ऑफिस को गंभीरता से लें। सीएम हेल्पलाइन और आरसीएमएस (राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर दर्ज मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। सोमवार देर शाम जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वसूली के संबंध में माइक्रो लेवल पर प्लान बनाते हुए राजस्व वसूली करें। साथ ही बड़े बकायेदारों की सूची बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि और किसान प्रमाण पत्रों की समय-समय पर समीक्षा करें। सभी उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत पटवारी चौकियों का समय-समय पर निरीक्षण करें। ताकि कहीं भी कोई पेडेंसी न रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि कतिपय मामलों में पटवारियों ने अंतिम रिपोर्ट जमा की हैं। संबंधित उप जिलाधिकारी एक बार अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा भली-भांति कर लें। जिससे कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व पुलिस चौकियों में स्थापित लॉकअप की भी जांच करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को उनकी कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी इला गिरि, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, प्रशिक्षु आईएएस दीक्षिता जोशी, उप जिलाधिकारी यमकेश्वर सीएस चौहान, उप जिलाधिकारी लैंसडौन शालिनी मौर्य, उप जिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी सतपुली अनिल चन्याल और तहसीलदार श्रीनगर धीरज राणा आदि ऑनलाइन जुड़े।

शादी का खाना खाकर बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचे

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : कुंभीचौड़ क्षेत्र में हुए एक शादी का खाना मोहल्ले वासियों को भारी पड़ गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उन्हें राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया। हालांकि, सभी की स्थिति सामान्य है। चिकित्सक बीमारी का कारण फूड प्वाइजनिंग बता रहे हैं। दो दिन पूर्व कुंभीचौड़ में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे थे। रात्रि भोज के बाद जब लोग अपने घर पहुंचे तो कईयों को उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगी। सोमवार को दो-चार लोग चिकित्सालय पहुंचे, जबकि कुछ ने घर के आसपास मेडिकल स्टोर से दवा ले ली। हालात में सुधार न होने पर मंगलवार को पीड़ित बेस चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती किया गया। अस्पताल में भर्ती एक महिला ने बताया कि अस्पताल में 15 से अधिक लोग एक ही मोहल्ले के हैं। इधर, हालात में सुधार होने पर कुछ लोगों को मंगलवार शाम तक चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई। जबकि पांच अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, बेस अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि लोगों में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बताया कि सभी बीमारों की स्थिति सामान्य है।

कोटद्वार अस्पताल में उपचार को पहुंचे लोग

अधिकारों के बजाय कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : मंगलवार को संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति आदि संगठनों ने गोष्ठी कर कई प्रस्ताव पारित किए। इस मौके पर प्रो. अनूप डोबरियाल ने कहा कि संविधान में हर सवाल का जवाब मिलता है। अधिकारों के बजाय हमें अपने कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है डॉ. बीजीआर परिसर के राजनीति विज्ञान विभाग में आयोजित गोष्ठी में परिसर निदेशक प्रो. यूसी गैरोला ने छात्र-छात्राओं को अधिकार एवं कर्तव्य पर व्याख्यान देते हुए कहा कि यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। आयोजक डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं, इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। वहीं, राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. कुमार गौरव जैन ने आधुनिक भारत के निर्माण में संविधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक डॉ. प्रकाश फोंदणी ने संविधान दिवस की विस्तृत रूप रेखा रखी। इन कार्यक्रमों में डॉ. दिनेश रावत, कल्पना रावत, पुनीत चंद्र वर्मा, सतवीर, खिलाफ सिंह, आलोक सिंह कंडारी आदि मौजूद रहे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बी.ई.एल. कार्यालय कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के सरकारी अभिलेखों में मेरा नाम मनोज कुमार अंकित है, जबकि मेरा सही नाम मनोज कुमार सनवाल पुत्र केशरचन्द्र सनवाल है।

मनोज कुमार सनवाल पुत्र केशरचन्द्र सनवाल निवासी शिब्बूनगर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(0578/21)

अदालती सूचना

न्यायालय श्रीमान असिसटेन्ट कलेक्टर कोटद्वार गढ़वाल

रा0वा0सं0 / 2023

श्रीमती लीलावती देवी पत्नी रामचन्द्र निवासी ग्राम लालपानी, सनेह, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल - वादिनी

बनाम

पुष्कर सिंह पुत्र स्व0 गुहार सिंह माता रमुली देवी, ललिता प्रसाद पुत्र बुद्धिराम, केशवानन्द पुत्र बुद्धिराम, आनन्दमणी पुत्र बुद्धिराम निवासीगण ग्राम लालपानी, सनेह, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल- आदि प्रतिवादीगण

हरगाह वादिनी एक वाद अन्तर्गत धारा 229 बी0 जमीदारी भूमि विनाश एवं भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत मेरे न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें आपको प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 4 बनाया गया है।

अतः आपको नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 29-11-2024 को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर जवाबदेही करें अन्यथा आपके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी।

दिनांक -

आज्ञा से

असिसटेन्ट कलेक्टर कोटद्वार

एक नजर

गुरिल्लाओं ने दी आत्मदाह की चेतावनी

श्रीनगर गढ़वाल : एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक कीर्तिनगर में की गई। बैठक में गुरिल्ला संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं टिहरी जिला अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गैरोला ने कहा कि नौकरी, पेंशन और आश्रित लाभ दिए जाने को लेकर गुरिल्ला 18 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। कहा कि सरकार 15 दिसंबर तक गुरिल्लों की मांगों पर अमल कर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर की सरकार ने वहां के गुरिल्लों को नौकरी, पेंशन 2004 में ही दे दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने कहा कि 30 नवंबर को श्रीनगर के काली कमली धर्मशाला में एक आवश्यक बैठक की जाएगी। जबकि 27 नवम्बर को प्रतापनगर और 5 दिसंबर को घनशाली के गैस गोदाम में आपातकालीन बैठक आयोजित की जाएगी। कहा कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लों की तीन सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वह सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश गैरोला, हिम्मत सिंह, बृजमोहन गुसाईं, हरिकृष्ण परमार, राजेंद्र भंडारी, लक्ष्मी देवी भट्ट, मुन्नी देवी, मधुसूदन, कमलेश मिश्रा, प्रताप भंडारी, दिवान सिंह, त्रेपन सिंह, इन्द्र मणि, रमेश दत्त लखेड़ा, बबिता देवी, अनिल लखेड़ा, राकेश बहुगुणा, रघुवीर लाल सहित आदि मौजूद थे।

ग्रामीणों ने ली बाहरी लोगों को जमीनें न बेचने की शपथ

नई टिहरी : मूल निवास भू-कानून जन आंदोलन समिति ने टिहरी के कुट्ठा गांव में ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बाहरी व्यक्तियों को जमीनें न बेचने की अपील की। मौके पर ग्राम देवता के सामने ग्रामीणों ने अपनी जमीनें न बेचने की शपथ भी ली। टिहरी के कुट्ठा में चलाए गए जागृति अभियान में गांव में तेजी से हो रही जमीनों की बिक्री पर चिंता जताई गई। इसके लिए ग्रामीणों के साथ समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय हुआ। भूम्याल देवता के मंदिर में ग्रामीणों ने शपथ ली कि वे आगे से बाहरी व्यक्तियों को जमीन नहीं बेचेंगे। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि जल्द ही गांव के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा। जिससे इस निर्णय को सार्वजनिक किया जा सके। गांव के प्रतिनिधियों ने भी यह भरोसा दिलाया है कि वे अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएंगे। गांव में यह बात भी सामने आई कि जमीनों को बेचने का काम खासकर वे लोग ही कर रहे हैं, जो पूरी तरह से यहां पलायन कर चुके हैं। समिति के लोगों ने जमीनों को बेचने का भविष्य में गंभीर खतरा भुगतना होगा। आम लोगों से मूल निवास को लेकर भी अपील करते हुए कहा कि सरकार से मूल निवास लागू करने के लिए लगातार मांग करें और समय पर इसके लिए किए जाने वाले आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भागीदारी भी करें। समिति के लोगों में संरक्षक महिपाल सिंह रावत, संयोजक देवेंद्र नौडियाल, अमित पंत, पर्वत कुमाईं, राहुल बुटोला आदि ने ग्रामीणों से इस अभियान को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि आसपास के लोगों व ग्रामीणों को भी इस मामले में जागरूक करें। (एजेंसी)

कर्मचारियों को दिलाई संविधान उद्देशिका की शपथ

नई टिहरी : संविधान दिवस के अवसर पर डीएम मयूर दीक्षित ने जिला कलक्ट्रेट परिसर में उपस्थित समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को भारत के संविधान उद्देशिका की शपथ दिलाई। उन्होंने सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को अपने कार्य-दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह्न करते हुए संविधान के मूल्यों व आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करने को कहा। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने भी जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस कार्मिकों संविधान की शपथ दिलाते हुए संविधान के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित किया। जबकि जीआईटीआई के छात्रों व नेहरू युवा केंद्र ने संयुक्त रूप से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए संविधान दिवस पद यात्रा निकालकर संविधान के निहितार्थ लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर सभी ने संविधान की देश के लिए महत्ता को बताते हुए संविधान के अनुरूप चलने की अपील की। इस मौके पर जिला कलक्ट्रेट में पीए चन्दन शाह, धीरेन्द्र पुण्डीर, कुशीराम डंगवाल, विनोद लाल, बालक राम, राजेश रमोला, राजेन्द्र, हीरा सजवाण, केशव गैरोला, खेमचन्द कुमाईं आदि मौजूद रहे।

आपदा के दौरान कराए गए कार्यों के बिल नही रहेंगे लंबित

स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा और बाल विकास विभाग प्राथमिकता से भवनों की मरम्मत करें

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव ने स्पष्ट किया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को त्वरित गति से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जिलाधिकारी डॉ. चौहान ने आयुक्त गढ़वाल मण्डल व सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह् देकर सम्मानित किया।

मंगलवार को गढ़वाल मंडल आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण संबंधी कार्य करवाने संबंधी मानकों में शिथिलता दी गई। इन कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि उनके पास जेसीबी और अन्य मशीनों के बिल भुगतान हेतु अवशेष हैं, तो उनको प्रमाण सहित जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित करें। विभागों से प्रस्ताव मिलने के बाद नए और पुराने बिलों का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्गत मानकों के संबंध में शंकाओं का भी समाधान किया। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पटवारी चौकियों की मरम्मत करा लें। यदि भविष्य में किसी माध्यम से या निरीक्षण में यह शिकायत मिलती है कि किसी भवन की स्थिति खराब है, तो संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग इंजीनियरों से स्थलीय निरीक्षण करवा कर स्टीमेट तैयार कर जिलाधिकारी को भेंजे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वालआयुक्त की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जाए। विभाग जल्द से जल्द उनके पास प्रस्ताव भेजें, जिससे संबंधित योजना पर कार्य करवाया जा सके। बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरूद्ध, सीडीओ गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी इला गिरी, एसीएमओ डॉ. पारूल गोयल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद शेट, उप जिलाधिकारी श्रीनगर नुपूर वर्मा, उप जिलाधिकारी लैंसडौन शालिनी मौर्य और उप जिलाधिकारी सतपुली अनिल चिन्याल सहित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मार्च 2025 तक तैयार होगा मालन पुल

बैठक में लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अधिशासी अभियंता ने बताया कि पौड़ी-कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमसौड़ के समीप भूस्खलन से बाधित हो रहे यातायात को देखते हुए कोटद्वार-चरेथ मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में मालन पुल के दो पिलर तैयार हो गए हैं तथा आठ पर कार्य चल रहा है। जल्द ही स्लैब डालने का काम भी शुरू करा दिया जाएगा। बताया कि मार्च 2025 तक पुल निर्माण की डेड लाइन निर्धारित की गई है। आगामी मानसून काल से पहले ही उक्त पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।

पुलिस ने शातिर ठग को सात मोबाईल फोन के साथ किया गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : पौड़ी पुलिस को एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से सात मोबाईल फोन बरामद किये है। अभियुक्त के खिलाफ पौड़ी जिले के पौड़ी, श्रीनगर, सतपुली, लैंसडौन और पैठाणी थाने में मुकदमा दर्ज है।

एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गत सोमवार को वादी सूरज सिह राणा, निवासी बुनका रतूडा, रुद्रप्रयाग ने कोतवाली पौड़ी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुद्रप्रयाग से पाबौ, पैठाणी जाने के लिए टैक्सी बुकिंग की गयी थी। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैश ना होने पर वादी को ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाने के नाम पर वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग गया, साथ ही वादी से गूगल पे द्वारा 23 हजार रूपये की धोखाधड़ी कर दी। जिस पर कोतवाली पौड़ी में आईपीसी की धारा 304(2),351(2), 352, 318(4) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना क्षेत्रान्तर्गत सायंकालीन चेकिंग के दौरान बुआखाल, गोरख्याखाल तिराहा के पास वादी सूरज सिह राणा द्वारा बताये गये हुलिया अनुसार मिलता जुलता एक संदिगंध व्यक्ति मिला, जो पुलिस से बचने की कोशिश कर एक दुकान में छिपने लगा। इस पर पुलिस टीम द्वारा तुरंत उस व्यक्ति की तलाशी ली गई। इस दौरान व्यक्ति से सात मोबाईल फोन बरामद हुए। जिस पर पुलिस टीम अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। जहां पुलिस पूछताछ में अभियुक्त पंकज पोखरियाल निवासी ओडागाड सांकरसैण, पाबौ, पौडी गढवाल ने बताया कि वह पौड़ी जिले में विभिन्न स्थानों से वाहनों को बुकिंक कर मोबाईल फोन छीनकर भाग जाता है। अभियुक्त द्वारा बताया कि वह शेयर मार्केट/बेटिंग मे पैसे लगाता है। वहां भारी नुकसान होने के कारण जनपद पौडी, देहरादून, रुद्रप्रयाग सहित विभिन्न स्थानो से वाहनों को बुक करके मोबाइल फोन छीनकर अपने अकाउंट मे पैसे ट्रांसफर करता है। लोगों से छीने 07 मोबाइलों को मैं बेचना चाहता था लेकिन उससे पहले मैं पकड़ा गया। पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक हेमकान्त सेमवाल, उपनिरीक्षक नवीन पुरोहित, उपनिरीक्षक राकेश चौधरी, आरक्षी प्रवीण पुरी, दिगम्बर सिंह, होमगार्ड हिम्मत सिंह, पीआरडी कुलदीप सिंह आदि शामिल थे।

डीएम ने कार्मिकों को दिलाई संविधान की शपथ

जयन्त प्रतिनिधि।

रूदप्रयाग : संविधान दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने संविधान दिवस की वर्षगांठ पर जिला कार्यालय परिसर में समस्त कार्मिकों को संविधान की शपथ दिलाई। इसके अलावा जनपद के अन्य विभागों में भी संविधान दिवस के अवसर पर संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया।

जिला कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय के समस्त कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष कई गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। जिला कार्यालय के अलावा संविधान दिवस के अवसर पर जिला सेवायोजन विभाग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज तिलक नगर में रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 130 से अधिक छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही अन्य विभागों में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 11 बजे संविधान दिवस की शपथ ली गई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी आशीष चंद्र घिल्डियाल, जिला सेवायोजन अधिकारी सुशील चंद्र चमोली, वैयक्तिक अधिकारी ओम प्रकाश बिष्ट, प्रधानाचार्य तिलक नगर डीएस राणा, प्रियंका भट्ट, रजनीश मैठाणी, श्रीकांत काला, जयकृत कंडवाल, किशन सिंह रावत सहित अन्य मौजूद रहे।

पीएम ग्रामीण आवास योजना के 3230 भवनों का काम पूरा

नई टिहरी : जनपद टिहरी गढ़वाल में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक कुल 3230 भवन बनाकर पूर्ण कर लिए गए हैं। जबकि पांच आवासों का निर्माण कार्य गतिमान है। ग्रामीण आवास योजना को लेकन मनाए गए ग्रामीण सप्ताह में पीएम ग्रामीण आवाज योजना को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया गया है।

परियोजना निदेशक डीआरडीए पीएस चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक जनपद को प्राप्त लक्ष्य 3 हजार 235 के सापेक्ष सभी लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करते हुए अब तक 3 हजार 230 आवास पूर्ण करा दिए गए हैं। शेष 5 आवासों का कार्य प्रगति पर है। बताया कि जो परिवार आवास से छूट गए हैं। उनका सर्वे किया जा रहा है। सभी 1034 ग्राम पंचायतों में सर्वेकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। जल्द ही भारत सरकार से जीओ टैग खुलने के बाद आवास स्वीकृति की कार्यवाही तेज की जाएगी। बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से आवास निर्माण के लिए अनुदान की धनराशि 1.30 लाख प्राविधानित है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) से तथा 95 दिनों के मजदूरी अंश का भुगतान मनरेगा से किए जाने का प्रावधान है। आवास स्वीकृत करने से पूर्व लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान तथा आवास निर्माण स्थल की जियो टैगिंग आवास ऐप के माध्यम से की जानी अनिवार्य है। आवास चयन एवं पंजीकरण के बाद धनराशि एफटीओ के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में आधार बेस सिस्टम के माध्यम से धनराशि हस्तानान्तरित करती है।

एमएसपी के अनुसार बने गारंटी कानून

रुद्रप्रयाग : अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी ने किसान आंदोलन को एक वर्ष पूर्ण होने पर तहसील मुख्यालय ऊखीमठ में धरना दिया। किसानों के सभी फसलों के लिए एमएसपी के अनुसार खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग की। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने तहसील कार्यालय ऊखीमठ में धरना दिया। उन्होंने सभी फसलों के लिए एमएसपी के अनुसार खरीद की गारंटी का कानून बनाने, किसानों के सभी कर्ज माफ करने, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26 हजार प्रतिमाह करने, मनरेगा में 200 दिनों का काम और प्रतिदिन मजदूरी 600 देने, बिजली बिल 2022 रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, जंगली जानवरों के आतंक पर रोक लगाने को ज्ञापन दिया गया।

संविधान दिवस पर राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की ली शपथ

जयन्त प्रतिनिधि।

थलीसैंण : मंगलवार को संविधान दिवस पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थलीसैंण में प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। इस मौके पर संविधान और हमारे जीवन में इसका प्रभाव विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा शोभा ममगांई, सुमन, बीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा संगीता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. विवेक रावत ने संविधान पर प्रकाश डाला। इसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका को स्मरण कराते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। प्रभारी प्राचार्य डॉ. बिपेन्द्र सिंह रावत ने संविधान दिवस के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे भविष्य का दर्पण है। बीते 75 वर्षों में हमने अपने संविधान के आदर्शों की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के माध्यम से ही भूमिहीन लोगों को जमींदारी प्रथा से मुक्त करवाकर उन्हें जमीने बांटी गयी। इस मौके पर डॉ. हरिओम रावत डॉ. अजय कुमार आदि मौजूद रहे।

यात्रा के सुचारूएवं सुगम संचालन को लेकर चर्चा की

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें यात्रा के सुचारू एवं सुगम संचालन को लेकर चर्चा की गयी। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टम्टा व जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर औचित्य के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। कहा कि जो भी प्रस्ताव बनाएं उसकी एक प्रति संबंधित विधायकों को भी अवश्य उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने पड़ावों के अनुसार कार्य योजना बनाने, यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, पार्किंग के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के उपचारात्मक कार्य आपदा मद से कराने के निर्देश दिए। वहीं उरेडा को यात्रा मार्ग पर खराब सोलर लाइटों की मरम्मत कराने को कहा। उन्होंने कहा संबंधित एसडीएम मुख्य भूमिका में रहेंगे और सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश देंगे। थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने कहा कि यह एक बड़ी यात्रा है हमने इस प्रकार कार्य योजना बनानी है जिससे श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक हो यह जिम्मेदारी हम सब लोगों की हैं उम्मीद करता हूं सब जिम्मेदारी से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से आग्रह किया कि किसी के पास अन्य सुझाव हैं जो हमारी यात्रा के लिए आवश्यक है तो उसकी कार्ययोजना भी शामिल की जाए। बैठक में पीडी आनन्द सिंह, नन्दा राजजात समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल, पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी व उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।

अधिकारियों ने ली संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की शपथ

दिल्ली : उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय में शपथ समारोह में भाग लिया। अधिकारियों ने संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की शपथ ली, जो राष्ट्र के संस्थापक दस्तावेज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।समारोह में भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना शामिल था, जो संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ौदा हाउस में सम्पन्न कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, जिसमें राष्ट्र के शासन में संविधान के महत्व पर जोर दिया गया। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष का समारोह विशेष महत्व रखता है क्योंकि उत्तर रेलवे न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करता है।

ब्रांड हाउस आफ हिमालयाज की 34.52 लाख की बिक्री

गत वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री के हाथों हुई थी हाउस आफ हिमालयाज की लांचिंग

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : पहाड़ के जंगलों में पैदा होने वाले शुद्ध शहद से लेकर सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाने वाला आर्गेनिक मंडुआ, झंगोरा, गहथ, राजमा और हैंडमेड ऊनी वस्त्र से लेकर हैंडिक्राफ्ट तक। विशुद्ध उत्तराखंडी उत्पादों का ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज', लांचिंग के एक साल से कम समय में 34 लाख रुपए से अधिक की बिक्री करने में कामयाब रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग के अधीन, हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की एकाएक मांग बढ़ी है। बीते 11 महीनों में ही हाउस ऑफ हिमालयाज कुल 34,52,330 रुपए की बिक्री दर्ज करने में कामयाब रहा है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद ऑफलाइन के साथ ही ई कामर्स साइट अमेजन और ब्रांड की खुद की अपनी वेबासइट पर भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए, गांवों की आर्थिकी मजबूत की जानी जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के परंपरागत उत्पाद अब देश विदेश में पहुंच रहे हैं, सरकारी खरीद के जरिए भी ब्रांड की मांग बढ़ाई जा रही है।

एक करोड़ सालाना बिक्री का लक्ष्य

सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा के मुताबिक उत्तराखंड की साठ प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ऐसे में हाउस ऑफ हिमालयाज ग्रामीण आर्थिकी के मामले में गेम चेंजर साबित होने जा रही है। योजना के तहत अगले तीन साल में कुल ब्रिकी करोड़ के पार पहुंचाते हुए, पांच लाख महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख के पार ले जाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय में 50 से 75 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

आठ श्रेणी में 35 उत्पाद

वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत आठ श्रेणी में कुल 35 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। सरकार स्थानीय मेलों, त्यौहार के मौकों पर हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को खरीदने पर जोर दे रही है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और कार्यालयों के जरिए भी हाउस ऑफ हिमालयाज की बिक्री बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382—222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com